स्वीकृत पैक्स

**६७,९०८**

किसानों को कवर किया गया

**१३ करोड़**

ऋण

**२.२ लाख करोड़**

गो लाइव

GO LIVE

**५९,११८**

दिन के अंत

**५७,३००**

ई-ऑडिट

**५५,२७६**

केवल इपैक्स

**२५, ७९४**




# इपैक्स का सरकारी पोर्टल के साथ एकीकरण

अधिक जानने के लिए स्कैन करें या आज ही पैक्स मोबाइल ऐप डाउनलोड करें !

/nabardonline

नाबार्ड

Ministry of Cooperation | सहकारिता मंत्रालय
Government of India | भारत सरकार

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

# केंद्र प्रायोजित पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु परियोजना

**एक जुड़े हुए भारत को सशक्त बनाना**

# पैक्स विकास की यात्रा

१

## १९०४

सहकारी ऋण समिति अधिनियम लागू किया गया; किसानों और कारीगरों को किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए जमीनी स्तर की संस्थाओं के रूप में पैक्स की स्थापना की गई

२

## १९१२

सहकारी समिति अधिनियम ने सहकारी संरचना और शासन को मजबूत किया।

३

## १९५४

अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने ग्रामीण ऋण वितरण की रीढ़ के रूप में पैक्स की सिफारिश की है।

४

## १९९०-२००० का दशक

- आदर्श सहकारी अधिनियम १९९१
- वैद्यनाथन समिति ने पैक्स के लिए वित्तीय पुनर्गठन और शासन सुधारों का सुझाव दिया।

५

## 2010 के दशक की शुरुआत

- नाबार्ड ने राज्य और जिला सहकारी बैंकों के लिए कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) शुरू किया
- ९७ वां सीएए, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा

६

## २०२१

देश भर में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई।

७

## २०२३

ईआरपी आधारित सॉफ्टवेयर का रोलआउट शुरू; हजारों पीएसीएस को शामिल किया गया और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

- परियोजना में विक्रेता ऑनबोर्डिंग - एनएलपीएसवी, सिस्टम इंटीग्रेटर, पीएमयू, हार्डवेयर
- विरासत अभिलेखों का डिजिटलीकरण
- ईपीएसीएस सॉफ्टवेयर का रोलआउट और पीएसीएस का ऑनबोर्डिंग
- लगभग १०,००० क्षेत्र स्तरीय संसाधन संवर्धन
- लगभग ३०० सुदृढ़ सहायता केंद्रों की स्थापना
- बुनियादी अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ३००० कोर/मास्टर प्रशिक्षकों का गठन और प्रशिक्षण

८

## २०२२

सरकार ने २०२७ तक ६३,००० से अधिक पैक्स को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए २,५१६ करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी।

९

## २०२४

**माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना का शुभारंभ, पैक्स ने सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिन के कार्य शुरू किए, ई-ऑडिट और सीएसपीसीपी के गुणात्मक पहलुओं की शुरुआत**

- टिकटिंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना
- महत्वपूर्ण मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी ) का निर्माण और प्रवर्तन - केवल इपैक्स, ई ऑडिट
- पैक्स अधिकारियों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना

१०

## २०२५

पैक्स को वित्तीय समावेशन और ग्रामीण सेवाओं के लिए बहुउद्देशीय केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई। राज्य सरकार द्वारा ईपैक्स सॉफ्टवेयर के उपयोग को अनिवार्य करने और दैनिक कार्यदिवसों का संचालन करने का आदेश

- मैन्युअल प्रणाली का अंत - सरकारी आदेशों द्वारा समर्थित
- केवल ईपैक्स घोषणाएँ
- ईआरपी गो-लाइव, कार्यदिवसों का समापन और ई-ऑडिट सहित सभी डिजिटलीकरण कार्यों में तीव्र प्रगति
- ९९% पैक्स को हार्डवेयर प्रदान किया गया और ईपैक्स सॉफ्टवेयर में उसका समावेश किया गया
- राज्य स्तरीय सॉफ्टवेयर अनुकूलन की परिपूर्णता
- पैक्स  की जियो-टैगिंग और जियो-कवरेज
- विस्तृत परियोजना डैशबोर्ड और निगरानी उपकरण

११

## २०२७

सभी स्वीकृत पैक्स के पूर्ण डिजिटलीकरण और परिवर्तन के लिए लक्ष्य वर्ष